

प्रेषक

डॉ. उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, देहरादून

गृह अनुभाग-8

देहरादून: दिनांक:- 27 मई, 2017

विषय:-जनपद देहरादून के स्थान जौलीग्रान्ट में एस.डी.आर.एफ के बहुउद्देशीय ब्लॉक एवं वायरलेस संचार हॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-दो-85/2015 दिनांक 05 मई 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ के बहुउद्देशीय ब्लॉक एवं वायरलेस संचार हॉल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 121/XX-8/1-04(46)2014 दिनांक 18.02.2016 द्वारा जनपद देहरादून के स्थान जौलीग्रान्ट में एस.डी.आर.एफ हेतु बहुउद्देशीय ब्लॉक एवं वायरलेस संचार हॉल का निर्माण कराये जाने के लिये कार्यदायी संस्था "उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि." इकाई-2 जनपद देहरादून, द्वारा उपलब्ध कराये गये रुपये 211.45 लाख के आगणन की औचित्यपूर्ण धनराशि रुपये 210.38 लाख में से पूर्व में अवमुक्त रुपये 200.00 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रुपये 10.38 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि में से उक्त कार्य हेतु अवशेष रुपये 10.38 लाख (रुपये दस लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि के भुगतान से पूर्व उक्त कार्य का अनिवार्य रूप से समवर्ती तकनीकी मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में प्राविधानित धनराशि रुपये 25.26 लाख (रुपये पच्चीस लाख छब्बीस हजार मात्र) के कार्यों हेतु "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008" के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। आगणन में "सेवा कर" हेतु प्राविधानित रुपये 9.57 लाख की धनराशि को भी इस धनराशि में सम्मिलित किया है।

4- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम

कमश:....2

अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

5- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

10- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

11- विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदयी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्रावधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधान में परिवर्तन(केवल अपरिहार्य सििति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

13- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

14- निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U. निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

15- निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

16- स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्रमशः.....3

16- निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10, के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211-पुलिस आवास, 08-स्टेट डिजार्स्ट रिस्पान्स फोर्स के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:- 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्या: S/705/00/97.....दिनांक 29 मई, 2017 द्वारा जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय

(डॉ. उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- बजट अधिकारी, साईबार कोषागार देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।
- 5- बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. इकाई-2 जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।
- 8- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव

